आर्थिक समीक्षा 2019-20 : प्रमुख तथ्य

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी, 2020 को संसद में आर्थिक समीक्षा, 2019-20 पेश की. आर्थिक समीक्षा 2019-20 के प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं:

धन सृजन : अदृश्य सहयोग को मिला भरोसे का सहारा

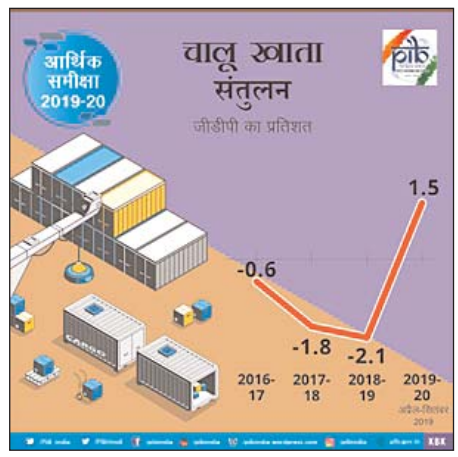

- आर्थिक इतिहास की तीन-चौथाई अवधि के दौरान वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में भारत का वर्चस्व इसे अभिव्यक्त करता है.
- कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' में किसी भी अर्थव्यवस्था में कीमतों की भूमिका के बारे में बताया गया है (स्पेंगलर, 1971).
- ऐतिहासिक दृष्टि से, भारतीय अर्थव्यवस्था ने भरोसे के सहारे के साथ बाजार के अदृश्य सहयोग पर विश्वास किया.
- बाजार का अदृश्य सहयोग आर्थिक लेन-देन में खुलेपन में प्रतिबिंबित हुआ.
- भरोसे का सहारा नैतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयामों में रेखांकित हुआ.
- उदारीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक मॉडल के उन दोनों ही स्तंभों को आवश्यक सहयोग दे रही है जिसकी वकालत हमारी पारंपरिक सोच में की गई है.
- आर्थिक समीक्षा में बाजार के अदृश्य सहयोग से प्राप्त हो रहे व्यापक लाभों के बारे में बताया गया है.
- उदारीकरण के बाद भारत की जीडीपी और प्रति व्यक्ति जीडीपी में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ-साथ धन सृजन भी हो रहा है.
- आर्थिक समीक्षा में बताया गया है कि बंद पड़े सेक्टरों की तुलना में उदार या खोले जा चुके सेक्टरों की वृद्धि दर ज्यादा रही है.
- अदृश्य सहयोग को भरोसे का सहारा देने की जरूरत है, जो वर्ष 2011 से वर्ष 2013 तक की अवधि के दौरान वित्तीय सेक्टर के प्रदर्शन से परिलक्षित होता है.
- आर्थिक समीक्षा में 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने संबंधी भारत की आकांक्षा का उल्लेख किया गया है जो निम्नलिखित पर काफी निर्भर है:
- बाजार के अदृश्य सहयोग को मजबूत करना
- इसे भरोसे का सहारा देना
- बिजनेस अनुकूल नीतियों को बढ़ावा देकर अदृश्य सहयोग को मजबूत करना
- नए प्रवेशकों को समान अवसर देना
- उचित प्रतिस्पर्धा और कारोबार में सुगमता सुनिश्चित करना
- सरकार के ठोस कदमों के जरिए बाजारों को अनावश्यक रूप से नजर अंदाज करने वाली नीतियों को समाप्त करना
- रोज़गार सृजन के लिए व्यापार को सुनिश्चित करना
- बैंकिंग सेक्टर का कारोबारी स्तर दक्षतापूर्वक बढ़ाना
- एक सार्वजनिक वस्तु के रूप में भरोसे का आइडिया अपनाना जो अधिक इस्तेमाल के साथ बढ़ता जाता है.
- आर्थिक समीक्षा में सुझाव दिया गया है कि नीतियां ऐसी होनी चाहिएं जो डेटा एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग के जरिए पारदर्शिता और कारगर अमल को सशक्त बनाएं.
- उत्पादकता को तेजी से बढ़ाने और धन सृजन के लिए एक रणनीति के रूप में उद्यमिता.
- विश्व बैंक के अनुसार, गठित नई कंपनियों की संख्या के मामले में भारत तीसरे पायदान पर.
- वर्ष 2014 के बाद से ही भारत में नई कंपनियों के गठन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है
- वर्ष 2014 से लेकर वर्ष 2018 तक की अवधि के दौरान औपचारिक क्षेत्र में नई कंपनियों की संचयी वार्षिक वृद्धि दर 12.2 प्रतिशत रही, जबकि वर्ष 2006 से लेकर वर्ष 2014 तक की अवधि के दौरान यह वृद्धि दर 3.8 प्रतिशत थी.
- वर्ष 2018 में लगभग 1.24 लाख नई कंपनियों का गठन हुआ जो वर्ष 2014 में गठित लगभग 70,000 नई कंपनियों की तुलना में तकरीबन 80 प्रतिशत अधिक है.
- आर्थिक समीक्षा में भारत में प्रशासनिक पिरामिड के सबसे निचले स्तर पर यानी 500 से अधिक जिलों में उद्यमिता से जुड़े घटकों और वाहकों पर गौर किया गया है.
- सेवा क्षेत्र में गठित नई कंपनियों की संख्या विनिर्माण, अवसंरचना या कृषि क्षेत्र में गठित नई कंपनियों की तुलना में काफी अधिक है.
- सर्वे में यह बात रेखांकित की गई है कि जमीनी स्तर पर उद्यमिता केवल आवश्यकता से ही प्रेरित नहीं होती है.
- किसी जिले में नई कंपनियों के पंजीकरण में 10 प्रतिशत की वृद्धि होने से सकल घरेलू जिला उत्पाद (जीडीडीपी) में 1.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है.
- जिला स्तर पर उद्यमिता का उल्लेखनीय असर जमीनी स्तर पर धन सृजन पर होता है.
- भारत में नई कंपनियों का गठन विषम है और ये विभिन्न जिलों एवं सेक्टरों में फैली हुई हैं.
- किसी भी जिले में साक्षरता और शिक्षा से स्थानीय स्तर पर उद्यमिता को काफी बढ़ावा मिलता है
- यह असर सबसे अधिक तब नजर आता है जब साक्षरता 70 प्रतिशत से अधिक होती है.
- जनगणना 2011 के अनुसार, न्यूनतम साक्षरता दर (59.6 प्रतिशत) वाले पूर्वी भारत में सबसे कम नई कंपनियों का गठन हुआ है.
- किसी भी जिले में भौतिक अवसंरचना की गुणवत्ता का नई कंपनियों के गठन पर काफी असर होता है.
- कारोबार में सुगमता और लचीले श्रम कानूनों से विशेषकर विनिर्माण क्षेत्र में नई कंपनियों का गठन करने में आसानी होती है.
- आर्थिक समीक्षा में यह सुझाव दिया गया है कि कारोबार में सुगमता बढ़ाने और लचीले श्रम कानूनों को लागू करने से जिलों और इस तरह से राज्यों में अधिकतम रोज़गारों का सृजन हो सकता है.
- आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने संबंधी भारत की आकांक्षा निम्नालिखित पर निर्भर करती है:
- बिजनेस अनुकूल नीति को बढ़ावा देना जो धन सृजन के लिए प्रतिस्पर्धी बाजारों की ताकत को उन्मुक्त करती है.
- सांठ-गांठ वाली नीति से दूर होना जिससे विशेषकर ताकतवर निजी स्वार्थों को पूरा करने को बढ़ावा मिल सकता है.
- शेयर बाजार के नजरिये से देखें, तो उदारीकरण के बाद व्यापक बदलाव लाने वाले कदमों में काफी तेजी आई
- उदारीकरण से पहले सेंसेक्स, में शामिल किसी भी कंपनी के इसमें 60 वर्षों तक बने रहने की आशा थी. यह अवधि उदारीकरण के बाद घटकर केवल 12 वर्ष रह गई.
- प्रत्येक पांच वर्ष में सेंसेक्स में शामिल एक तिहाई कंपनियों में फेरबदल देखा गया जो अर्थव्यवस्था में नई कंपनियों, उत्पादों और प्रौद्योगिकियों की निरंतर आवक को दर्शाता है.
- प्रतिस्पर्धी बाजारों को सुनिश्चित करने में उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद सांठ-गांठ को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने अर्थव्यवस्था में मूल्य पर अत्यंत प्रतिकूल असर डाला:
- वर्ष 2007 से लेकर वर्ष 2010 तक की अवधि के दौरान आपस में संबंधित कंपनियों के इक्विटी इंडेक्स का प्रदर्शन बाजार के मुकाबले 7 प्रतिशत सालाना अधिक रहा जो आम नागरिकों की कीमत पर प्राप्त असामान्य लाभ को दर्शाता है.
- इसके विपरीत वर्ष 2011 पर इक्विटी इंडेक्स का प्रदर्शन बाजार के मुकाबले 7.5 प्रतिशत कम रहा जो इस तरह की कंपनियों में अंतर्निहित अक्षमता और मूल्य में कमी को दर्शाता है.

2. ईसीए के तहत औषधि मूल्य नियंत्रण

- डीपीसीओ 2013 के जरिए औषधियों के मूल्यों को नियंत्रित किए जाने से नियंत्रित दवाओं की कीमतें अनियंत्रित समान दवाओं की तुलना में ज्यादा बढ़ी.
- सस्ती दवाओं के फॉर्मुलेशन की कीमत खर्चीली दवाओं के फॉर्मुलेशन से ज्यादा बढ़ी.
- इसने इस बात को साबित किया कि डीपीसीओ ने सस्ती दवाओं की उपलब्धता के जो प्रयास किए वे उल्टे रहे.
- सरकार दवाओं का एक बड़ा खरीददार होने के कारण सस्ती दवाओं की कीमतें कम करने के लिए दबाव डाल सकती है.
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को सरकार की ओर से दवाओं की खरीद का सौदा अपने हिसाब से करने के इस अधिकार का पारदर्शी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए.

3. खाद्यान्न बाजार में सरकार के हस्तक्षेप

- खाद्यान्न बाजार में सरकारी हस्तक्षेप के कारण, सरकार गेहूं और चावल की सबसे बड़ी खरीददार होने के साथ ही सबसे बड़ी जमाखोर भी हो गई है.
- निजी कारोबार से सरकार का हटना
- सरकार पर खाद्यान्न सब्सिडी का बोझ बढ़ना
- मार्केट की अक्षमताएं बढ़ने से कृषि क्षेत्र का दीर्घावधि विकास प्रभावित
- खाद्यान्न में नीति को अधिक गतिशील बनाना तथा अनाजों के वितरण के लिए पारंपरिक पद्धति के स्थान पर नकदी अंतरण - फूड कूपन तथा स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल करना.

4. कर्ज माफी

- केंद्र और राज्यों की ओर से दी जाने वाली कर्ज माफी की समीक्षा
- पूरी तरह से कर्ज माफी की सुविधा वाले लाभार्थी कम खपत, कम बचत, कम निवेश करते हैं जिससे आंशिक रूप से कर्ज माफी वाले लाभार्थियों की तुलना में उनका उत्पादन भी कम होता है.
- कर्ज माफी का लाभ लेने वाले ऋण उठाव के चलन को प्रभावित करते हैं.

(पसूका)